SYNOPSIS शोध रूपरेखा

1. प्रस्तावित शोध का विषय –

''छत्तीसगढ़ राज्य में ''खनिज साधन विभाग'' के प्रबंधन व संगठन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन'' (2003 – 2013 तक)

2. प्रस्तावना :–

खनिज संसाधन मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधारभूत स्तंभ माने जाते है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी प्राकृतिक संपदा के दोहन पर निर्भर करती है। प्राचीन काल से ले कर वर्तमान तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में खनिजों का उपयोग निरंतर किसी ना किसी रूप में होता चला आ रहा है। राष्ट्र की आर्थिक संरचना पर औद्योगीकरण का विशिष्ट प्रभाव पडता है, इसलिए आधुनिक भारत के शिल्पी पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''भारत के उद्योग एवं कारखाने ही इसके तीर्थ स्थल एवं मंदिर हैं।" इस कथन से औद्योगिक विकास की आवश्यकता एंव महत्व स्पष्ट है।

"आकर प्रभवः कोष" अर्थात खान कोष का स्त्रोत हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की यह उक्ति आज की परिस्थितियों में भी खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रासंगिक है। आज के औद्योगिक युग में खनिज संसाधनों की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता।

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से इसका संपूर्ण राष्ट्र में द्वितीय स्थान है। इस नवसृजित राज्य में औद्योगिक महत्व के खनिजों यथा कोयला, लोहा, बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट के विशाल भंडार मौजूद है। इनके अतिरिक्त आर्थिक महत्व का खनिज स्वर्ण, सामरिक महत्व का खनिज टिन अयस्क तथा रत्न सम्राट हीरा भी यहां पाया जाता है। इस प्रदेश का 44% से अधिक भाग वनप्रान्तरों से आच्छादित है, तथा अधिकांश खनिज पदार्थ इन्हीं वनप्रान्तरों एवं पहाड़ियों में पाये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। प्रदेश में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाते है जिनमें बहुमूल्य रत्न भी सम्मिलित है। प्रदेश पूरे राष्ट्र में एकमात्र टिन

उत्पादक राज्य है, तथा इसे विश्व के बेहतरीन लौह अयस्क धारित राज्य की उपाधी व गौरव भी प्राप्त है। राज्य में कोयले के 50846 मिलियन टन भण्डार है व राष्ट्र के कुल कोयला उत्पादन में राज्य की सहभागिता 21.10% है। लौह अयस्क भण्डार राष्ट्रीय लौह अयस्क का 18.21% योगदान दे रहा है।

3. शोध अध्ययन का उद्देश्य :—

1. छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास में खनिज साधन विभाग का योगदान ज्ञात करना।
2. राज्य में उपलब्ध खनिजों के अन्वेषण एवं विकास के बारे में जानना।
3. खनिज साधन विभाग की नीतियों एवं दायित्वों का अध्ययन।
4. खनिज साधन विभाग की विस्तृत कार्यप्रणाली, आर्थिक (वित्त) संरचना, संगठन व प्रबंध संरचना का अध्ययन।
5. राज्य के उपलब्ध विभिन्न खनिजों से प्राप्त उपलब्धियों का अध्ययन।
6. खनिज साधन विभाग की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं सुझाव।

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ को आज ″खनिज का कटोरा″ ″रत्नगर्भा छत्तीसगढ़″ आदि विशेषणों से विभूषित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अपने खनिज भण्डारों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। बस्तर का लोहा जापान को निर्यात करने के लिए रेल सेवा विशाखापट्नम बंदरगाह तक उपलब्ध करा दी गई है, जापान के सहयोग से यह सेवा प्रारंभ हो पायी जो सिर्फ इसलिए की गई, कि करोड़ों रूपये का कच्चा लोहा भारत निर्बाध गति से उसे भेजता रहे।

छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अंतर्गत संचालनालय भौमिक एवं खनिकर्म मुख्यालय के रूप में रायपुर में, क्षेत्रिय कार्यालय बिलासपुर व जगद्लपुर में स्थित है। खनिज के सर्वेक्षण कार्य को गुणात्मक बनाने के लिए मुख्यालय रायपुर व क्षेत्रिय कार्यालय बिलासपुर व जगद्लपुर में रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं। राज्य में कुल 27 जिला कार्यालय शामिल है। अधिनियमों के आधीन गठित मण्ड़ल तथा निगम छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड है।

खनिजों के अन्वेषण एवं उनका विकास विभाग का मुख्य कार्य है, इसके अंतर्गत प्रदेश में नये खनिज धारित क्षेत्रों का विस्तृत मूल्यांकन , सर्वेक्षण एवं उनका सीमांकन करना है। अन्वेषण एवं उनके विकास में नवीन प्रयोगों की संभावना है ऐसी परिस्थिति में खनिज साधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी ? विभाग के अन्वेषण कार्यक्रमों के प्राथमिकता से चलाए जाने से नये खनिज धारित क्षेत्र प्रकाश में आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्याप्त उत्खनन के साथ ही खनिज आधारित

उद्योगों की स्थापना हो रही है। क्या इन उद्योगों में रोजगार के नये अवसर के साथ ही उन क्षत्रों का समग्र विकास संभव हो पा रहा है। विभाग के इन कार्यकलापों के विस्तृत अध्ययन हेतु मैं इस पर शोध प्रबंध लिखने हेतु आकृष्ट हुई हूँ।

4. चयनित विषय में पूर्व शोध कार्य का संक्षिप्त सिंहावलोकन :–

''छत्तीसगढ़ राज्य में ''खनिज साधन विभाग'' के प्रबंधन व संगठन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन'' इस विषय में शोध कार्य आरंभ करने के पूर्व इस विषय से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में हुए शोध कार्यों का सिंहावलोकन इस अध्याय में किया गया है।

Bowmans Creek (1980's,)

"Hunter Valley and Newcastle Coalfields"

Author examined that Coal mining in the Hunter Valley region has been ongoing for years, and the region suffers the combined impacts of both longwall and open cut mining. In the 1980's, Bowmans Creek (near Singleton) underwent extensive water loss due to mining induced subsidence as well as an increase in salinity in areas where flow returned (Total Environment Centre, 2007). South Wambo Creek and Stoney Creeks are cracked due to mining at the Homestead Colliery. Coal extraction occurred at epths between 80 and 240 metres, resulting in both creeks becoming dry for the majority of the year, and the channel bed to become filled with approximately 5 metres of sand (Dawkins, 1999). At the lower mining depth of 80 metres, the surface cracks and goaf areas became connected, resulting in significant surface water flow directly into the mine and subsequent flooding. There was no surface water flow into the mine for mining depths greater than 100 metres (Dawkins, 1999). Other impacted creeks in the Hunter areas are Glennies Creek, EuI Creek, Fishery Creek, Black Creek and Foy Brook (Total Environment Centre, 2007).

Stoner (1983)

Author's study concluded that the impact of mining on the hydrological systems was localised with regard to the mining front, with the most significant hydrological impacts occurring during the period of maximum subsidence. At this location the shallow aquifer system was isolated from the major fractured zone directly above the mine by the intermediate aquiclude zone. Stoner (1983) formed a conceptual model of the hydrogeological impacts of longwall mining based on field results from a site in Greene County, Pennsylvania. Stoner (1983) found that as a general rule the magnitude of water

level decline was expected to be inversely proportional to the thickness of bedrock between the mine and well bottom.

सोनी आर. पी. (1991)

''भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्रान्तर्गत स्थित दल्ली – राजहरा, नंदिनी, हिर्री खदानों के श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण''

लेखक ने अपने शोध कार्य में यह बताया है कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण इन क्षेत्रों में वहां काम करने वाले श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में खनिज संसाधनों का क्या योगदान है। विकास की अपार संभावना युक्त खनिज खदानों में किस प्रकार श्रमिकों से कार्मिक कार्य प्रणाली अपनायी जाती है, उनकी सुरक्षा, विकास के कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम का संपादन सफलता पूर्वक किया जाता है।

श्रीवास्तव सूर्यकांत (1993)

''बस्तर संभाग की खनिज संपदाओं पर आधारित उद्योगों की आर्थिक संभावनाएं''

लेखक ने शोध में बताया है कि बस्तर संभाग प्राकृतिक संपदा से संपन्न एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जहां विकास की गति धीमी है। बस्तर संभाग में उद्योगों के लिए भरपूर संभावनाएं है, यहां उद्योगों के आर्थिक विकास के लिए उपर्युक्त प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। अध्ययन उपरान्त सुझाव दिया गया कि जिले में औद्योगिक विकास से ही वहां रोजगार व आर्थिक विकास की समस्या हल होगी। वास्तव में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र की गरीबी व बेकारी को मिटा कर क्षेत्र को समृद्धि व संपन्नता की ओर ले जाया सकता है।

दुबे अल्पना (1996)

''छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग में श्रम कल्याण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का तुलनात्मक अध्ययन''

लेखक ने अपने शोध में यह परिकल्पना की है कि सीमेंट उद्योग में श्रम कल्याण की स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का तुलना में बेहतर है। तकनीकी क्रांति के इस युग में इन उद्योगों को नई ऊचाइयों तक ले जाया जा सकता है, श्रम की विशेष भूमिका रहेगी। उद्योगों एवं शासकीय प्रयास से अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न कर श्रमिकों के हालत में सुधार किया जा सकता है। तकनीकी प्रशिक्षण से जन हानि

को रोका जा सकता है। सरकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन से उद्योग के विकास को अपेक्षित गति मिल सकती है।

बेगानी कमल कुमार

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास : विश्लेषणात्मक अध्ययन''

लेखक के अनुसार आर्थिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में व्यापारिक, औद्योगिक, आण्विक महत्व के खनिजों का भंडार है। बैलाड़िला के उच्च कोटि का लौह अयस्क का जापान में निर्यात हो रहा है, अगर उनका उपयोग भारत में किया जाए तो भिलाई जैसे दो बड़े इस्पात और स्थापित किसे जा सकते है। शोध अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास प्रतिवर्ष 10–12% प्राप्त की जाती है, खनिज संसाधनों के व्यवस्थित दोहन से राज्य के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।

Jefferson County (USGS, 1996)

"Illinois Coal Basin"

Jefferson County, in Illinois Coal Basin, has been the focus of a number of studies (Booth, 2006; Booth, 2003; Booth, 2002; Booth, 1999; Booth and Bertsch, 1999; Karaman et al., 1999; Booth et al.,1998). Booth (2006) described a mine consisting of 4, 183 metres wide by 1,530 metres long panels, 3 metres thick at a depth of 222 metres. At this site, ground subsidence rapidly reached 2 metres along the panel centreline and there was considerable strata fracturing, particularly shear fractures along the tensional margins of the subsidence trough and vertical bedding separation in the central trough area. The permeability increased by an order of magnitude and levels in the overlying sandstone aquifer declined as the mine face approached, and then partially recovered during the compressional stress phase (Booth 1999; Booth et al., 1998).

Booth and Bertsch, (1999).

"Saline County"

Booth (2006) summarised the impacts of longwall mining at a site in Saline County, in the Southern Illinois Coal basin. At this site six adjacent longwall panels were mined in a 2- metres-thick coal seam, between 97 and 122 metres deep and 204 and 287 metres wide.

Sidle et al., (2000)

Author examined to described a site in Utah, where longwall coal mining occurs at depths of approximately 300 metres. Siddle et al., (2000) found increases in the length of cascades and pool volumes with longwall mining. However, these increases were short lived, and the volumes and numbers of pools declined significantly. Recovery of the streams and channels was noted as occurring a year after the initial subsidence effects were noted. The study did not continue for long enough to comment on the extent of recovery

पाठक बबीता (2001)

''रायपुर संभाग में खनिज आधारित उद्योगों का विकास, समस्याएं एवं संभावनाएं''

लेखक ने अपना अध्ययन रायपुर संभाग के खनिज आधारित उद्योगों पर प्रकाश डाला है। राजधानी रायपुर के विकास एवं राजधानी के अनुरूप निर्माण कार्यक्रमों के लिए रायपुर के आस पास उद्योगों का एक बड़ा सिलसिला आरंभ होगा। जिसमें खनिज आधारित उद्योग शामिल होंगे। विकास की समस्या के रूप में स्थानों की क्षतिग्रस्त भूमि, स्थानीय लोगों का विरोध, वन संरक्षण अधिनियम 1980, कोयले की कीमत में नियंत्रण समाप्त कर देने से भिन्न – भिन्न कीमत पर कोयले की उपलब्धता उभर कर सामने आयी। उपाय के रूप में बताया गया कि जहां उत्पादन के मुख्य घटक मौजूद हों उन्ही स्थान पर संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके व एवं मांग में वृद्धि का जा सके।

शुक्ला पूर्णिमा (2002)

''छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन विकास एवं नियोजन एक भौगोलिक अध्ययन''

लेखक ने खनिज संसाधन के विकास एवं नियोजन पर अध्ययन करने पर पाया कि खनिज की प्रचुरता वाले क्षेत्र कम विकसित हैं जबकि संसाधन वाले क्षेत्र विकसित हैं अर्थात खनिजों का क्षेत्रिय उपयोग कम हो रहा है। समस्याओं के निम्न सुझाव दिये गये :–

1. प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में रखने के लिए राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए।
2. राज्य का परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया जाए।
3. लोहा, स्पंज आयरन एवं उर्जा प्रक्षेत्र के अलावा एल्युमिनियम, रिफेक्ट्री, कटिंग, पालिशिंग संयंत्र में भी निवेश किया जाए।

सारस्वत आशा (2002)

''छत्तीसगढ़ के खनिज आधारित उद्योगों का विकास एवं संभावनाएं''

लेखक के शोध का उद्देश्य यह है कि विकास की प्रक्रिया का तीव्र गति से संचालन व विकास योजना बनाने के पूर्व आवश्यक होता है उस क्षेत्र प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की प्रकृति व गुणों का अध्ययन किया जाए। प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं है। खनिज आधारित उद्योगों का विकास में खनन को मुख्य समस्या के रूप में पाया गया। खनन की कुछ नीतियां अव्यावहारिक व लोचहीन हैं जो खनिज उद्योग के विकास के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। नियमों में व्यावहारिक परिर्वतन से विकास में वृद्धि की जा सकती है।

Stout (2004)

Conducted the study in headwater streams in northern West Virginia, USA, to measure the extent of longwall mining impacts on headwater streams and to determine if they recover after cessation of mining. The study compared the physical (width and temperate), chemical (conductivity, dissolved oxygen, alkalinity, pH and hardness) and biological (macro invertebrate) characteristics of streams impacted by long wall mining to similar references streams, which were not impacted. Data was collected over a 2-year period, and where possible compared to historic data over a ten-year period Significant physical differences in longwall mined versus reference streams included 0.8.

साहू हेमलता (2005)

''रायपुर संभाग के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग केन्दों का योगदान''

लेखक द्वारा दुर्ग जिले के विभिन्न खनिज आधारित उद्योग केन्द्रों के योगदान का अध्ययन किया गया। यहाँ उद्योगों के समक्ष निम्न समस्याएं पायी गयीः–

1. समग्र योजना का अभाव
2. आधारभूत सुविधाओं की कमी
3. दोषपूर्ण संगठनात्मक संरचना
4. शासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की कमी

निम्न सुझाव दिये गयेः–

1. सुविधाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार
2. श्रमिकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था
3. ऋण प्रकिया का सरलीकरण
4. उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करना

5. प्रस्तावित कार्य में सहयोगी क्षेत्र :–

खनिज साधन विभाग अपने अधीनस्थ संचालनालय भौमिक एवं खनिकर्म मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, व कंपनी अधीनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन 07 जून 2001 को किया गया है, जिनका मुख्य कार्य खनिजों के पट्टे प्राप्त कर खनिजों का विकास, उचित दोहन एवं विक्रय कर लाभ अर्जित करना तथा राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लोक कल्याणार्थ कार्य करना है। इन सभी विभाग का मेरे शोध कार्य में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व योगदान रहेगा।

6. प्रस्तावित शोध प्रविधि :–

शोध प्रविधि शब्द का आशय शोध के संबंध में अपनायी जाने वाली विभिन्न विधियों के तार्किक व औचित्यपूर्ण प्रयोग से है। शोध प्रविधि जहाँ एक ओर विचारार्थ विषय के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित कर करने वाली हो, वही लोचपूर्ण हो ताकि जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना संभव हो। अध्ययन आर्थिक हो या सामाजिक या व्यावसायिक समस्या से पहले उसकी पूर्व योजना प्रारंभ से ही बना ली जाती है ताकि विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त किया जा सके। इस परिप्रेक्षय में खनिज साधन विभाग की संगठन संरचना व उपलब्धियों के मूल्यांकन करने हेतु अनुसंधान योजना को दो वर्गों में विभक्त किया गया है।

प्रथम :– खनिज साधन विभाग की प्रकाशित पत्र – पत्रिकाएं, प्रतिवेदन तथा विभागों के संरक्षित अभिलेखों से सामाग्री, आंकडों का संकलन करना।

द्वितीय :– क्षेत्र सर्वेक्षण, विषय सामाग्री की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना, निर्धारित प्रश्नावलीयों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। व्यक्तिगत संर्पक एवं साक्षात्कार के माध्यम से विषय

संबंधित सूचनाओं व आंकडों का संग्रहण, विश्लेषण करना। प्रबंध के प्रस्तुतीकरण में विभिन्न सांख्यिकीय मापों, अनुपात निर्वेचन तथा सारणीयन विधि, रेखीय संगठना विधि तथा आरेखीय चित्रण आदि से संबंधित गणितीय सूत्रों का स्थिति विश्लेषण किया जायेगा । शोध प्रविधि पर्याप्त लोचपूर्ण होगी ।

7. शोध परिकल्पना :–

प्रस्तावित शोधकार्य छत्तीसगढ़ राज्य में ''खनिज साधन विभाग'' के प्रबंधन, संगठन व्यवस्था, एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

प्रस्तावित शोध कार्य में परिकल्पना की गई है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से परिपूर्ण, एक संपन्न राज्य होते हुए भी आर्थिक रूप से विपन्न है ।
2. राज्य में उपलब्ध अकूत, प्राकृतिक संपदा एवं खनिज संपदा के पर्याप्त दोहन से राज्य के आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है ।
3. खनिज संपदा के दोहन में पिछड़े वर्ग की उचित भागीदारी से राज्य का व अविकसित क्षेत्रों का विकास संभव है ।
4. खनिज संपदा युक्त पिछडे संभागों का विकास, आर्थिक एवं समाजिक विकास द्वारा संभव है।

8. प्रस्तावित शोध कार्य के अपेक्षित निर्गम :–

छत्तीसगढ़ राज्य नवगठित राज्य है जहाँ पर अपार प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी पिछडे क्षेत्रों के संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन व राज्य में उपलब्ध खनिजों का समुचित विकास एवं उपयोग नहीं हो पाता जाता है। पिछड़े एवं नक्सलवाद ग्रसित क्षेत्रों में विकास हेतु आत्मनिर्भता आवश्यक है। प्रस्तुत शोध कार्य से खनिज साधन विभाग में स्थानीय व विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं में वृद्धि व उसका लाभ स्थानीय लोगों को सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में शाधार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज साधन विभाग के संगठन, प्रबंधन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जायेगा। किये जाने वाले शोध कार्य को निम्नांकित नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नुसार है :–

शोध प्रबंध की रूपरेखा :—

चयनित विषय – ''छत्तीसगढ़ राज्य में ''खनिज साधन विभाग'' के संगठन, प्रबंधन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन'' (2003 से 2013 तक)

प्रथम अध्याय :— प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि

1.1 वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य

1.2 शोध परिकल्पना

1.3 शोध प्रविधि

1.4 शोध अध्ययन की सीमाएँ

1.5 शोध अध्ययन का क्षेत्र

1.6 शोध साहित्य का पुनरावलोकन

द्वितीय अध्याय :— छत्तीसगढ़ एक सामान्य परिचय

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक परिपाश्विक दशाएँ

2.2 भू–भौतिकी संरचना, जलवायु, संसाधनिक समृद्धि, भूगर्भिक संरचना

2.3 आर्थिक परिवेश

2.4 छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, भू–जल स्त्रोत, जलसंसाधन की वर्तमान भूमिका

2.5 परिवहन एवं संचार सुविधा

2.6 जनसंख्या वितरण

2.7 मानव संसाधन

तृतीय अध्याय :— खनिज संसाधन एक परिचय

3.1 भारत में खनिज की स्थिति

3.2 छत्तीसगढ़ में खनिज की स्थिति

3.3 खनिज साधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं वित्त व्यवस्था, महत्व एवं लक्ष्य

3.4 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, संगठनात्मक स्वरूप अधिकार एवं कार्यक्षेत्र

चतुर्थ अध्याय :– छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों का उत्पादन

4.1 राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधन के प्रकार

4.2 क्षेत्रवार उत्पादित खनिज संसाधन

4.3 खनिज आधारित उद्योगों से उत्पादन

पंचम अध्याय :– खनिज साधन विभाग की संगठनात्मक संरचना एवं प्रबंधन का स्वरूप

5.1 संगठन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य

5.2 खनिज साधन विभाग की संगठनात्मक संरचना

5.3 प्रबंधन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य

5.4 खनिज साधन विभाग की प्रबंध व्यवस्था एवं प्रबंधकीय कार्य प्रणाली

षष्ठम अध्याय :– छत्तीसगढ़ राज्य शासन की खनिज नीति एवं उद्देश्य

6.1 राष्ट्रीय खनिज नीति

6.2 राज्य खनिज नीति

6.2.1 अधोसंरचना तथा मानव संसाधन का विकास

6.2.2 गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास

6.2.3 संस्थागत विकास व नियमों का परिशोधन

सप्तम अध्याय :– खनिज साधन विभाग की उपलब्धियों का मूल्यांकन

7.1 खनिज संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ

7.2 सार्वजनिक एवं निजि क्षेत्र से प्राप्त खनिज राजस्व

7.3 राज्य के मुख्य खनिजों से राजस्व प्राप्तियां

7.4 शीर्षवार एवं जिलेवार राजस्व प्राप्तियाँ

अष्टम अध्याय :– खनिज साधन विभाग का आर्थिक विकास में योगदान

8.1 राज्य के आर्थिक विकास में योगदान

8.2 राज्य के सामाजिक विकास में योगदान

8.3 राज्य के खनिज का विनिमयन एवं निर्यात

नवम अध्याय :– खनिज साधन विभाग की समस्याएँ एवं सुझाव एवं समीक्षात्मक निष्कर्ष

9.1 विकास की संभावनाएँ

9.2 विकास में आने वाली समस्याएँ

9.3 समस्याओं के सुझाव एवं समीक्षात्मक निष्कर्ष

संदर्भित ग्रंथ सूची (BIBLIOGRAPHY)

1.	अग्रवाल, आर. सी.	–	व्यवसाय प्रशासन एवं प्रबंध (नवयुग साहित्य आगरा)	2006
2.	अग्रवाल, जी.के.एवं पाण्डेय, एस. एन.	–	शोध सांख्यिकी साहित्य भवन पब्लिकेशन	2004
3.	भारत शासन नई दिल्ली	–	भारत की खनिज संपदा	
4.	बंसल, एस. पी.	–	विपणन प्रबंध के सिद्धांत कल्याणी पब्लिशर्स	2007
5.	भंडारी, डॉ. बी. एस.	–	विपणन प्रबंध यूनिवर्सल पब्लिकेशन, आगरा	2006
6.	दुबे, आर.एन.एवं सिन्हा, वी.सी.	–	आर्थिक विकास एवं नियोजन (नेशनल पब्लिकेशन हा.न.दि.)	2002
7.	गुप्ता, मदन लाल	–	छत्तीसगढ़ दिग दर्शन (भारतेन्दु हिन्दी साहित्य समिति)	2002
8.	गुप्ता डॉ. के. एल.	–	भारत की आर्थिक संस्याएँ नवयुग साहित्य सदन, आगरा	2004
9.	जैन, बी. एम.	–	शोध प्रविधि व क्षेत्रीय तकनीक (रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर.)	2001

10. कोटलर, फिलिप	–	मार्केटिंग मैनेजमेंट	2005
11. कुलश्रेष्ठ, बी.एन.	–	आधुनिक भार जनजीवन व संस्कृति कमल प्रकाशन इंदौर	2000
12. लेखी, आर. के.	–	व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत कल्याणी पब्लिशर्स	2009
13. मुखर्जी रविन्द्रनाथ	–	सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी विवेक प्रकाशन दिल्ली	2006
14. राव., के वी.	–	रिसर्च मैथडोलाजी इन कामर्स एंड मेनेजमेंट	2009
15. आर. सी अग्रवाल एवं एन. एस. कोठारी	–	भारतीय कंपनी अधिनियम साहित्य भवन पब्लिकेशन	2011
16. त्रिवेदी, डॉ. आर. एन. शुक्ला	–	रिसर्च मैथडोलाजी	
17. त्रिपाठी, बद्री विशाल	–	भारतीय अर्थव्यवस्था (किताब महल, इलाहाबाद)	2000
18. त्रिपाठी कौशलेन्द्र	–	छत्तीसगढ़ का भूगोल शारदा प्रकाशन बिलासपुर	2001
19. सक्सेना, कृष्ण सहाय एवं गुप्ता के. एल.	–	औद्योगिक अर्थशास्त्र (नवयुग साहित्य सदन, आगरा)	2006
20. शुक्ला, शांता	–	छत्तीसगढ़ का सामाजिक विकास (नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली)	2005

21. शर्मा आर. के. व गुप्ता – व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत कल्याणी पब्लिशर्स 2009

22. तिवारी, विजय कुमार – छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन हिमालय पब्लिशिंग हाउस मुम्बई 2001

छत्तीसगढ़ संचालनालय, भौमिक एवं खनिकर्म, रायपुर द्वारा प्रशकाशित पुस्तकें

1. भारत की खनिज संपदा भारत शासन नई – दिल्ली
2. छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा एवं खनिज आधारित उद्योग
3. खनिज सांख्यिकी 2009 एवं 2012
4. खनिज रियायत निर्देशिका
5. मिनरल रिसोर्सेस एंड मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़
6. खनिज नीति
7. खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली
8. मिनरल रिर्सोसेस एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़
9. खान एवं खनिज (विनिमय तथा विकास)
10. खनिज रियायत नियम

प्रकाशित शोध ग्रंथ –

1. डॉ. अशोक शुक्ल, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, युगबोध प्रकाशन रायपुर।
2. डॉ. पी. एल मिश्रा, दि पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर।
3. डॉ. आशा सारस्वत, छत्तीसगढ़ के खनिज आधारित उद्योगों का विकास एवं संभावनाएँ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याालय रायपुर।
4. डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन विकास एवं योजनाएं, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याालय रायपुर।

5. डॉ. संजय गुहा, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधन की विश्लेषणात्मक अध्ययन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
6. डॉ. सुनयना पारख, छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में खनिज संसाधन एवं उस पर आधारित उद्योगों का योगदान।

प्रतिवेदन एवं सर्वेक्षण :—

1. वार्षिक रिर्पोट 2010—11 एवं 2011—12, 2012—13 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2009—10, 2010—11 एवं 2011—12, 2012—13 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली
3. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2011—12, 2012—13, 2012—13 छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, रायपुर
4. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2011—12, 2012—13 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर
5. मौलिक लेख योजना।

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं :—

1. छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन — शिक्षादूत प्रकाशन, रायपुर
2. खान संपदा — खान मंत्राालय नई दिल्ली
3. मौलिक लेख योजना — खान मंत्राालय नई दिल्ली
4. परिकल्पना '2010' — छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, रायपुर
5. नवभारत — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
6. दैनिक भास्कर — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
7. देशबंधु — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
8. पत्रिका — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
9. नई दुनिया — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
10. हरिभूमि — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर
11. इस्पात टाईम्स — दैनिक समाचार पत्र, रायपुर

12. प्रतियोगिता दर्पण – भारतीय अर्थव्यवस्था, उपकार प्रकाशन

वेबसाइट :–

1. www.mines.nic.in
2. www.chhattisgarh.nic.in
3. www.chhttisgarhmines.gov.in
4. www.ministryofmines.in
5. www.mines.nic.in
6. www.chhattisgarh.gov.in

The Synopsis is hereby forwarded to the Research Degree Committee for kind approval

निर्देशक
डॉ. एच. एस. भाटिया
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नेहरू महाविद्यालय,
डोंगरगढ (छ.ग.)

सह निर्देशक
डॉ. एस.एस.खनूजा
प्राचार्य
दुर्गा महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
श्वेता तिवारी
सहायक प्राध्यापक
महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल
महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

The Synopsis is hereby forwarded to the Research Degree Committee for kind approval

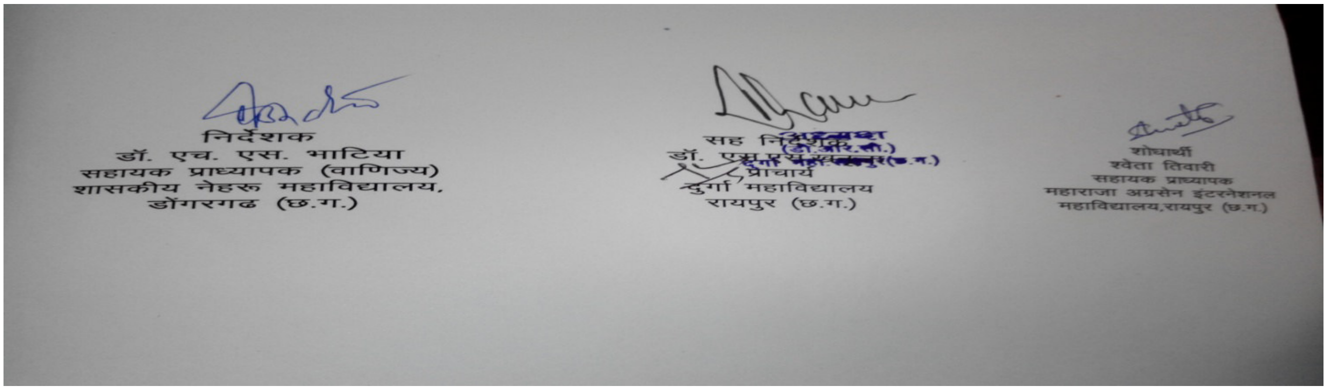
निर्देशक
डॉ. एच. एस. भाटिया
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नेहरू महाविद्यालय,
डोंगरगढ (छ.ग.)

सह निर्देशक
डॉ. [illegible]
प्राचार्य
दुर्गा महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
श्वेता तिवारी
सहायक प्राध्यापक
महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल
महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)